कापियां खाली छूटती गयीं। उसमें करोड़ों रुपये वसूल किए गये और वसूल करने के बाद एक विशेष जिले के लोगों को पिछले दो वर्षो में भर्ती करने का क्रम जारी रहा। जब आखिरी किश्त मोहम्मद गजनवी के तरीके से लूटकर यह सारे लोग जा रहे थे, चेयरमैन, सैक्रेटरी और उसके मैंम्बर्स तो सी0बी0आई0 को इसकी इनफॉर्मेशन मिली और ट्रेन में से उतरते हुए उनकी अटैचियों की तलाशी ली गयी जिनमें लाखों रुपये बरामद किये गये। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया किन्तु वह एक दूसरा प्रकरण है। परन्तु ढाई क्विटल चांदी तो वह दिल्ली के बाजार में आकर बेचकर चले गये। लोगों के करोड़ों रुपये लिए गये और इस प्रकार सारे देश में जितने भी भर्ती बोर्ड बने, उनके अंदर एक प्रक्रिया अपनाई गयी और एक विशेष स्थान से लोगों का पिछली बात गत सरकार के द्वारा, चयन किया गया। महोदय, भर्ती बोर्डों के मैम्बर कैसे अप्वायंट किये गये थे, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे एक सज्जन मिलने के लिए आए और उन्होंने आकर कहां " मंत्री जी नमस्कार"। उन्होंने कहा "आप आ गए" रेलवे भर्ती बोर्ड के मैम्बर बन जाइए।

"You will be glad to know that Ministry of Railway have decided to place your name on the panel of the non-official member of the Railway Recruitment Board. For being associated with the Interview Committee, representative of backward classes, you are requested to please get in touch with the Chairman of the Railway Recruitment Board, who is being advised to obtain you b1o-data for completing necessary formalities."

बायोडाटा नहीं, ऐप्लीकेशन नहीं , जानकारी नहीं, आने वाला नहीं और उसको वहां पर मैम्बर, अप्वायंट कर दिया गया। इस प्रकार मेरा निवेदन है कि लाखों लोगों से करोड़ों रुपये लूटे गये। मैं चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के नियमों में परिवर्तन किया जाए और यू0पी0एस0सी0 के द्वारा भर्ती बोर्डों के मैम्बर और चेयरमैन का चयन किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐडमिनिस्ट्रेटिव उच्च स्तरीय जांच की जाए, इन सारे भर्ती बोर्डों के पिछले दो साल के कार्यकलापों की ओर जो करोड़ों रुपये लूट लिये गये हैं तथा जिन लोगों के वह लूटे गये हैं उनको रुपया वापिस कैसे लौटाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था हो। मैं सदन के सामने एक विशेष प्रकार का घटनाक्रम इस विशेष उल्लेख के जरिए लाना चाहता था। मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

Issue of Chandigarh

श्री बरजिन्दर सिंह (पंजाब); सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं। पहले जब बम पर डिस्कशन हुआ था तब मेरा नम्बर भी आया था लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नाम काट दिया गया और दूसरे साहिबान को जो मेरे साथी थे, बोलने का मौका दिया गया। ये तो जस्ट एक बात है।

आपने जो मुझे बोलने के लिए टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद । यहां मैं चण्डीगढ़ के बारे में बात करना चाहता हूं। होम मिनिस्टर श्री आडणणी जी ने लोक सभा में रिटर्न रिप्लाई में जो कहा कि चण्डीगढ़ यूनियन टेरिटरी रहेगा, इससे बहुत से पंजाबियों को, जो अलग सैक्शन वाले पंजाबी हैं, उनको धक्का लगा है। We never expected from the Home Minister this because we always demanded that Chandigarh should be given to Punjab.
पंजाब में अकाली और भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है और सेन्टर में भी अकाली –भाजपा के साथ गवर्नमेंट चला रहे है। हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जो बयान छपा है उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा-

The Punjab Chief Minister said, "It is unfortunate that successive Central Governments have continued to ignore our legitimate claims. Chandigarh belongs to Punjab and in this we are not seeking any special concession from the Centre." According to him both the law as well as the past precedents dictated that in any division of State the existing Capital always remains in the parent State.

यह बात उन्होंने उस वक्त कही जब उनके साथ उनके साथी बीजेपी के जो मिनिस्टर थे वे भी बैठे हुए थे। मैं कुछ मिनटों में, पंजाबियों की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें पंजाबियों का जो हिस्सा रहा, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । मुझे यह कहने में पूरा गर्व है और मैं गौरव महसूस करता हूं कि पंजाब ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत हिस्सा लिया। वहां बहुत सी मूवमेंट है, अकाली मूवमेंट है, कम्युनिस्टों की मूवमेंट है, गदर मूवमेट है और किसानों की इतनी मूवमेंट चली है कि उन सब में पंजाबी शहीद हुए। उस वक्त जितनी उम्र कैद पंजाबियों की हुई है उससे हमारा सिर गौरब से ऊंचा हो उठता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिफोर पार्टिशन , 1947 से पहले जो पंजाब था आज उसका सिर्फ 20 परसेंट ही यहां बचा है। 1996 में पंजाब का डिविजन हुआ तो इंक्लूडिंग चंडीगढ़ तो यह

लम्बी कहानी है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं वे पंजाब से बाहर निकाल दिये गये। तो बात यह हुई कि जब होलोकास्ट हुआ सन् 47 में, लाखों लोग वहां मर गये, बेघर हो गए, यहां उजड़कर आ गए तो पं0 नेहरू जो हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर रहे उनके मन में एक सपना था कि पंजाबियों का जिनका कैपिटल लाहौर उनसे बिंछड़ गया है या जिसे व छोड़ आए है या जो उनका हिस्सा नहीं रहा, उनको जरूर एक कैपिटल बनाकर दिया जाएगा। उन्होंने दो काम किये। एक हमें भाखड़ा डैम दिया और दूसरा चण्डीगढ़, जो ड्रीम लेते थे, उन्होंने यह दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि यह दोनों चीजें आज पंजाब से छीन ली गई है । इसके पीछे बहुत बडीई कहानी है, बहुत सी पोलिटिकल चीजें है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । मैं तो यह कहूंगा कि जो इनजास्टिस पंजाबियों के साथ, हमारे साथ लगातार इन इश्युज पर होता आया है, कैपिटल जो हमारी है, जो हमें मिलनी चाहिये वह अब सेंटर का हिस्सा है। वह भी हमसे छिन गया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के पिछले 10-12-15 साल हमारे बहुत दुखद, मैं यह कहूंगा कि एगोनी के दौर से गुजरे हैं, हमने वह सब कुछ झेला है। हमारे सामने जो खून बहा है पंजाब की धरती पर, जो ज़ख्म पजाब के सीने पर लगे है, वह हमने सारे देखे है। मैं समझता हूं कि ऐसा रीपीट नहीं होना चाहिये। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी, वह पंजाब की कुछ डिमांड्ज के बारे में थी। पहले डिमांड्ज अकाली पार्टी और दूसरी पार्टियों ने की। वह डिमांड्ज़ जब नहीं मानी गई तो कम्पलीकेटेड सिचुयेशन होती गई। उसका नतीजा बल्यु स्टार आप्रेशन, फौज का हमला अमृतसर दरबार साहब में, उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद 1984 के रायट हुए। बहुत ही दुखद दौर हमने देखा है। पंजाब ने अपने सीने पर यह दुखद दौर झेला है लेकिन उसके बाद राजीव लौंगोवाल अकार्ड हुआ। मूझे अफसोस है कि उस अकार्ड को भी इम्पलीमेंट नहीं किया गया। स्पष्ट लिखा था कि फलां तारीख को चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा लेकिन राजीव जी ने वह भी नहीं किया और अभी तक राजीव लौंगोवाल अकार्ड वैसे ही रहा है और चण्डीगढ़ हमें नहीं मिल सका है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा पिछले जो स्टेट असेम्बली के इलेक्शन पंजाब में हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों अलाई थे। उन्होंने इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, जो सब अखबारों में भी छपा, पेम्फेलेट भी छपे। उनमें भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब यूनिट है उसने यह कहा कि विद दॉ कनसेंट आफ सेंट्रल लीडरशिप एंड दॉ पार्टी इस विषय इलेक्शन लड़ा गया कि Chandigarh and other Punjabi-speaking areas belong to Punjab. They should be given to Punjab. ? लेकिन अब हमें यह हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है और पंजाब में अकालियों के साथ उनका गठजोड़ है, हमारे होम मिनिस्टर साहब यह स्टेटमेंट दे रहे है। इसका मतलब यह है कि यह अब पंजाब को नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह पंजाब के साथ, हमारे साथ बेइन्साफी है। चण्डीगढ़ एंड अदर पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ पंजाब को मिलने चाहिये हरियाणा और हिमाचल हमारे भाई है। हमारा इनका प्यार, हमारा इनका लेन-देन है। मैं समझता हूं कि चण्डीगढ़ और अदर पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ पंजाब को देने की बात पर आपस में बैठ कर सेंटर और स्टेट्स को हल निकालना चाहिये। मैं उम्मीद करता था कि विद दि गवर्नमेंट यह मसला हल होगा लेकिन तीन महीने के बाद भी मैं महसूस करता हूं कि इन स्टेट्स का जो झगड़ा है उसको निपटाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। पंजाब में भी भापजा अकाली सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा अकाली अलाई हैं और हिमाचल में तो भाजपा की सरकार है। मैं यह समझता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियेटिव लेगी इन स्टेटों को बुला कर जो उनके पेंडिंग मसले है उनको हल करेगी लेकिन मेरा ख्याल है कि आने के बाद एक कदम भी इस तरफ नहीं बढ़ाया गया है। अपनी खिंचाव पैदा करने की कोशिश बन जाएगी, जिसको हम पूरी तरह से अपोज़ करते है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश): मैं सरकार बरजिन्दर सिंह जी ने चंडीगढ़ के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

मैं एक ही शब्द कहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने यह नया इश्यू खड़ा कर दिया। यह तो झगड़ा खत्म हो चुका था। इसमें तो इंप्लीमेंटेशन में हेराफेरी या झिझक दिखायी गई है। फैसला हुआ था 25 जनवरी की रात और 26 जनवरी, 1986 की सुबह को कि चंडीगढ़ पंजाब के हवाले कर दिया जाएगा। यह फैसला हो चुका था राजीव-लौगोवाल एकार्ड में, पार्लियामेंट में, उस सदन में, लोक सभा में और इधर। इसको यूनिनैमसली एप्रव कर दिया गया था। तो मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने यह नया विवाद शुरू कर दिया एक हल हो चुके मसले को दुबारा शुरू करके। जो देश के हित में नहीं, पंजाब के हित में नहीं, हरियाणा के हित में नहीं।

दो भाईयों की तरह जो मसला हल हो रहा था उसमें गड़बड़ पैदा की है।

मैं अपने आपको सरदार साहब से एसोसिएट करता हूं।

Economic blockage of National Highways No. 39 and 53

SHRI W. ANGOU SINGH (Manipur):

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for allowing mc to raise a special issue for saving the lives of the people of Manipur.

Sir. Manipur is a land-locked State. There is no water-way or railway to reach the St; c. The National Highways arc the only life-line for the State of Manipur. There are two National Highways. One, the National Highway No. 39, passes through Nagaland. Another, the National Highway No. S3, passes through Assam, Silchar. Nowadays the National Highway No. S3 is not in a proper condition to be utilised. The National Highway No. 39 is the only life-line for the State of Manipur now.

The present position is that this National Highway has been blocked by launching an economic blockage by two Naga organisations, the Naga National Council and the Naga Students Union, who arc opposing the creation of a separate Sadar Hill (Kangpokpi) District in Manipur. This blockage is continuing from the 21st of May, 1998.

The creation of the Sadar Hill (Kangpokpi) District is the common demand of all the regional and national level parties in the State. The Creation of the separate Sadar Hill (Kangpokpi) District has been included in the election manifestos of all the parties.

The present Government has decided to create this district. On hearing that the Naga organisation, the Naga National Council and the Naga Students Union proposed the economic blockage of the National Highway. The present Chief Minister called a meeting of all the parties to discuss about the creation of the Sadar Hill (Kangpokpi) District. All the parties took a decision to request the Naga organisations to withdraw the blockage, but the Naga organisations have rcfuesed it.

Now, the present position is that all the trucks carrying essential commodities and oil tankers have been damaged "on the way when they are coming to approached the capital of Manipur, Imphal. The truck owners resolved not to ply on this road without Security. Because of this the people of Manipur are now not able to receive essential commodities. In order to save them from this state of affairs, I would request the hon. Home Minister to take immediate measures so that the essential commodities safely reach Manipur.

Another appeal to the Central Government is thai the Government of India should recruit National Highway Security Force so that they can be utilised for protection of National Highways where there is absence of railways in the border state like Manipur.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): We have nine more speakers. We will permit two minutes to each speaker. Just make suggestions, so that the Minister can reply to you. Wc have already debated enough on it. Shri Raghavji.

SHORT DURATION DISCUSSION

Alarming Deterioration in Power and Water Supply Situation in the Country Contd.—

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं अपनी बात को केवल पेयजल की समस्या तक सीमित रखूंगा। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि प्राणी की जीवन रक्षा के लिए वायु और जल नितांत आवश्यक है । वैसे इस पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है और पृथ्वी का दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा जल से आच्छादित है, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस में समुद्र का खारा पानी 97.4 परसेंट है, बर्फीले स्थान पर 1.8 परसेंट और पीने योग्य पानी सिर्फ 0.8 परसेंट है और इसी कारण यह समस्या उत्पन्न होती है।

मान्यवर, देश को आजाद हुए 50 वर्स को गए है, लेकिन स्थिति यह है कि 31.12.97 को यहअनुमानित